

प्रेषक,

के०डी०भट्ट,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
लोक सेवा अधिकरण, उत्तराखण्ड
316, फैज-II, बसन्त विहार,
देहरादून।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 17 मार्च, 2015

विषय- लोक सेवा अधिकरण उत्तराखण्ड देहरादून में संयुक्त निबन्धक (सिविल जज, सीनियर डिवीजन
वेतनमान में) के पद की निरन्तरता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-14/उ०लो०से०अधि०/प्रशा०-IV दिनांक 12-01-2015
के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 168/XXXVI/2011-326/2011
दिनांक 01-09-2011 द्वारा पुर्नजीवित/सृजित संयुक्त निबन्धक का 01 पद की निरन्तरता वर्तमान शर्तों
एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचनाके पहले ही समाप्त न कर दिये जाय, दिनांक
01-03-2015 से 29-02-2016 तक बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-04 के
अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-04-लोक सेवा अधिकरण-
00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-1270/76-दस दिनांक 20 जुलाई 1968
सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-877/दस-92-24(8)/92 दिनांक 07-11-1992 (यथा उत्तराखण्ड
राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये
जा रहे हैं।

भवदीय

(के०डी०भट्ट)
प्रमुख सचिव

संख्या-63(1)/XXXVI(1)/2015-326/2001 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा देहरादून।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 3- वित्त अनुभाग-5/कार्मिक अनुभाग/एन०आई०सी०/गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(राकेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव